EDITORIAL

NITI AAYOG AND ITS INITIATIVES

The entire BSNL folk were in appreciable mood when we heard the observations of Our Prime Minister Shri Narendra Modiji, on the day of Independence about the successful turnaround of BSNL and its operational profit. Unfortunately the news that is coming in the name of NITI AYOG thro media is disturbing us. All that we expect is transparency and fair discussion taking us into confidence on any issue affecting us, the main stakeholder.

The National Institution for Transforming India Aayog (NITI Aayog) was established by the Modi Government on Jan 2015 by replacing the 50 years old Planning Commission the one served by many great minds of India. The spirit told was cooperative federalism, giving importance to States and their needs.

NITI Aayog inturn had constituted subgroups and taskforces to study on various issues and suggest the same to the Govt for appropriate actions. The centrally sponsored schemes were reduced with some umbrella schemes and schemes like swatch Bharath also initiated. As a responsible citizen and Trade Union , we should watch and react accordingly and welcome , if things are for the welfare of our people. But our main concern is about PSU and about our BSNL.

As a Think Tank of Government of India,NITI Aaayog is also entrusted with some other initiatives like studying analysing and suggesting the future of PSUs. In the name of Vision, strategies beyond 2017, NITI Aayog had constituted a committee under the chairmanship of Dr Arvind Panagariya on sick, loss making, non performing CPSUs on march 2016. The committee has made its recommendations in respect of 74 CPSEs. The main recommendations are closure of 26 companies, strategic disinvestment in 10 companies and revival with disinvestment for 22 companies and **sale or transfer to State Government for 6 companies**. Naming of the companies and case by case recommendations are not available for public information.

We come to know that on October 2016, the cabinet had given its approval to strategic sale of some companies and the names of the companies would be revealed only at the time of auction. DIPAM, department of investment and Public Asset Management would chalk out plan for this. But during June-July of 2016 media were reporting about the strategic sale of BSNL and MTNL and the same was denied by the press statement of NITI Aayog appeared in the Statesman daily .

The other disturbing factor is now whether BSNL is in the list of the 6 PSUs marked for sale or transfer to state govt. The letter sent from Office of PMO signed by Deputy secretary Mayur Maheswari IAS to the Secretary DOT is causing us serious concern. The letter is seeking the implementation status for the closure, transfer to State regarding BSNL and ITI from the DOT. What are the recommendations of NITI Aayog after analyzing the finances of BSNL? Whether the full report is given to DOT as well as BSNL? What are the aspects that made NITi Aaayog to transfer the biggest all India entity like BSNL to State and reducing its status as a kind of State entity? What are the bigger designs? These are some questions that need transparent discussion.

Our NFTE Chq will monitor the developments and try its level best to forge unity of all Unions and associations to fight our right cause of defending our bread winner, the great edifice BSNL. Let us be vigilant and gird up our loins to face the onslaughts and Government moves to dismantle BSNL.

संपादकीय

नीति आयोग और उसकी पहल

जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणियों पर आजादी के दिन बीएसएनएल के परिचालन लाभ की सफल बदलाव के बारे में सुनने के बाद बीएसएनएल के लोक प्रशंसनीय मूड में थे। हम मुख्य हितधारक होते हुये, जो बाते नीति आयोग के नाम पे मिडिया में हो रही है उससे हम प्रभावित हो रहे है। हमें प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर हमें विश्वास में लेते हुए पारदर्शिता और निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए।

ऐसा बताया गया की, सहकारी भावना, संघवाद और राज्यों को उनकी जरूरत को महत्व देने के मध्य नजर रखते हुए 50 साल पुराना योजना आयोग जिनमें बहुत बड़े लोगों ने योगदान दिया हुआ था, उसको बदलने के नीति आयोग की स्थापना की।

नीति आयोग ने सरकार को सही सुझाव देने के लिए उपसमुहों और विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए टास्कफोर्स गठित किया। केंद्र द्वारा आयोजित कुछ योजनाओं को भंग करके, स्वच्छ भारत जैसे नई योजना लाई गयी। अगर यह चीजे लोगों की हित में होगी, तो हमें जिम्मेदार नागरिक और संघटनों के रूप में हम इन्हें देखना चाहिये और, स्वागत करते हुए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पर हमारी चिंता का विषय पीएसयू और बीएसएनएल है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भविष्य के बारे में सुझाव और अध्ययन हेतु भारत सरकार ने एक–थिंक–टँक के रूप में नीति आयोग को ये कार्य सौंपा। दूर दृष्टि के नाम पर बीमार और नुकसान में रहने वाले सीपीएसयू के बारे में रणनीतियों को बनाने के नाम पर डॉ. अरविंद पानग्रहीया की अध्यक्षता में समिति गठित की। इस समिति ने 74 केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगों के संबंध में राय दी थी। मुख्य सिफारिशों में 26 कंपनियों को बंद करने के लिये, 10 कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश और 22 कंपनियों का पुर्नगठन विनिवेश के साथ की है। और इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गयी।

हमें यह मालूम हुआ है, अक्टूबर 2016में मंत्रिपरिषद ने कुछ कंपनियों की रणनीतिक बिक्री के लिए अपनी मंजूरी दी थी और इन कंपनियों को नाम केवल नीलामी के समय ही पता चलेगा। डीआईपीएएम, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के विभाग को यह योजना बनानी होगी। 2016 की जून–जुलाई के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल की रणनीति बिक्री के बारे में मिडिया रिपोर्टिंग कर रहे थे लेकिन नीति आयोग ने उसे नकारा था। वह नीति आयोग का बयान स्टेटसमन दैनिक में आया था।

हमें यह चीज परेशान कर रही है, जीन 6 पीएसयूएस की सूची राज्य सरकार को हस्तांतरण के लिए चिन्हीत है, उसमें बीएसएनएल शामिल है या नहीं। इस बारे में पीएम ऑफिस से श्री मयुर महेश्वरी (आयएएस) के हस्ताक्षर से डिओटी की भेजी हुई चिट्ठी हमारे चिंता का विषय बनी हुई है। यह चिट्ठी में बीएसएनएल और आइटीआइ के बारे में कार्यान्वयन स्थिति की मांग की गयी है।

बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के बाद नीति आयोग की सिफारिशें क्या है? क्या पूरी रिपोर्ट डॉट और बीएसएनएल को दी या नहीं? वैसे कौन से पहलु है, जो बीएसएनएल जैसी सबसे बड़ी भारत निकाय (All India Entity) को राज्य में बांटने की (स्थानांतरित) नीति आयोग अपनी नीति बना रहा है? और इसके अलावा कौन सी नीति है? ऐसे कुछ सवाल है जिसके बारे में पारदर्शि चर्चा होनी की आवश्यकता है।

हम इन घटनाओं पर नजर रखे हुए है। हमारी रोजी–रोटी को बचाने के लिए और बीएसएनएल रक्षा हेतु, सभी संगठनों और यूनियनों की एकता के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे।

बीएसएनएल को तोड़ने की सरकार की मनशा को नाकामयाब करने के लिए हमें सदैव सतर्क रहना होगा।